बढ़ते हुए शहरीकरण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

3399. **श्री सोमपाल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1994 के "इकोनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत को बढ़ते हुए शहरीकरण के विरुद्ध सावधान किया है;

(ख) क्या विश्व बैंक का यह विचार सही है कि इस प्रकार के शहरीकरण तथा शहरों में रह रही जनसंख्या से भविष्य में जल, भूमि और वातावरण पर असह्य बोझ पड़ने वाला है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सिलसिले में एक दीर्घकालीन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) यह एक जाना-माना तथ्य है कि शहरीकरण और जनसंख्या का केन्द्रीकरण का सामान्यत: जल संसाधनों, भूमि तथा पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। भारत भी इस का अपवाद नहीं है। तथापि, यह कहना कि यह दबाव "असह्य" होता है, साबित करने के लिए विस्तृत आंकलन उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) शहरी विकास राज्य का विषय होने के नाते, इस विषय पर कोई दीर्घकालिक नीति तैयार करने से, पूर्व राज्य सरकारों और संघ राज्यों के विचार जानना आवश्यक होगा। इस बाबत् राज्य सरकारों से परामर्श की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी है।

Subletting premises on Government allotted land

3400. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of Institutions which have been found guilty of illegal earnings from letting out their premises built on Government allotted land during each of the last three years in each of the metropolitan cities;

(b) how many of them have been penalised for the misuse of the premises in violation of the terms and conditions mentioned in the allotment letters;

(c) what preventive steps have been taken to stop these irregularities; and

(d) what action has been taken against such defaulters and what amount of penalities have been imposed and recovered from them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Prices of Land in Delhi

3401. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to unstarred question 6172 given in the Rajya Sabha on 6th May, 1994 regarding fixation of land rates in Delhi and state:

(a) what are the reasons for which the complete information asked for in part (a) of the question has not been supplied;

(b) whether the information was not readily available with the Ministry; and

(c) if so, will the Minister lay on the Table of House a copy each of the statements giving information relating to the period ending 31st March, 1994, 31st March, 1990 and 31st March, 1980?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (c) Information is being gathered and will be placed on the Table of the Sabha soon.

Anomalies in Conversion Scheme from Lease Hold to Free Hold

3402. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Delhi High Court has recently directed the Ministry of Urban